http://amritkalashtimes.com

अमृत कलश टाइम्स

वर्ष : 18
अंक : 74

प्रयागराज शनिवार 30 नवम्बर 2024

पृष्ठः- 4, मूल्यः- एक रूपया

पीएम करेंगे पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत

नई दिल्ली,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से एक दिसंबर तक ओडिशा में भुवनेश्वर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार यह सम्मेलन आज शुरू हो रहा है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, नारकोटिक्स सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर विचार–विमर्श होगा। सम्मेलन के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सम्मेलन देश के वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों और साथ ही भारत में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, ढांचागत और कल्याण संबंधी समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से चर्चा तथा बहस करने के लिए एक संवाद–मंच प्रदान करेगा। इस क विचार–विमर्श में आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा अपराध नियंत्रण और कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पेशेवर प्रथाओं और प्रक्रियाओं को तैयार करना और साझा करना शामिल होगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राज्य मंत्री (गृह मामले), राज्योंध्केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सहित अन्य लोग भाग लेंगे।

'कुंदरकी में उल्टा तीर सपा को लगा'

● योगी बोले- रामवीर के लिए खूब बजी तालियां, खन्ना जी प्रचार की बताकर गोवा चले जाते थे

लखनऊ,(एजेंसी)। विधानसभा में नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसके बाद बीजेपी विधायकों का भाजपा दफ्तर में सम्मान किया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में सबसे ज्यादा ताली कुंदरकी के विधायक रामवीर सिंह ठाकुर के लिए बजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यकर्ताओं और मंत्री की भी मेहनत है। जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलेंगे तो हम 2027 में और जोरदार सफलता हासिल करेंगे। विपक्ष केवल आरोप लगाएगा। विपक्ष दूर–दूर तक नजर नहीं आया। कुंदरकी के बारे में अनेक आशंकाएं थीं, जो हमें जाति के नाम पर लड़ाते थे उनको ही उल्टा तीर जाकर लगे। सीएम ने कहा जब हम सब टीम भावना के साथ एकजुट होकर काम करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है, वो ऐतिहासिक है। उपचुनाव की पहली बैठक में प्रत्याशी तय नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने लक्ष्य तय किया कि कम से कम 7 सीट हम जीतेंगे। मंत्रियों ने घर का काम समझकर जिम्मेदारी निभाई सीएम ने कहा कि धर्मपाल जी एक–एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिन मंत्रियों को जिस सीट की जिम्मेदारी दी गई, उन लोगों ने अपना घर का काम समझ कर जिम्मेदारी निभाई है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कुंदरकी और कटेहरी में भाजपा का झंडा गाड़ने का काम किया गया। नए विधायको से मैं कहूंगा कि जनता से बेहतर तालमेल बनाकर चलें। 2027 के विधानसभा चुनाव की यह शुरुआत है। इस परिणाम ने विपक्ष के मन मे भय पैदा कर दिया है। आरोप–प्रत्यारोप लगते रहेंगे, जिन्हें एनडीए ने मौका दिया उन्हें कार्यकर्ताओ ने विजयी बनाने का काम किया। विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ता लगाए गए उन्होंने खूब काम किया। भाजपा के सामने विपक्ष दूर–दूर तक दिखाई नही पड़ रहा है। करहल–सीसामऊ में 2027 में कमल खिलाएंगे योगी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है करहल और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त 67 से 68 हजार थी, अब वह घटकर 13 हजार पर आ गई है। 2027 में हम वहां कमल खिलाएंगे। मानना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। सीसामऊ में अंतिम क्षण में भाजपा 7 से 8 हजार में हारी। कोई भी सफलता हमे एक प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। असफलता एक चुनौती होती है। 2027 में एक बार फिर यूपी में कमल खिलेगा। भूपेंद्र चौधरी बोले– कटेहरी और कुंदरकी में बड़ी जीत मिली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह सामान्य विजय नहीं है। कई सीटें ऐसी थीं, जिस पर भाजपा नहीं जीत पा रही थी।

सीसामऊ में 2027 में कमल खिलाएंगे

● योगी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है करहल और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त 67 से 68 हजार थी, अब वह घटकर 13 हजार पर आ गई है। 2027 में हम वहां कमल खिलाएंगे। मानना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। सीसामऊ में अंतिम क्षण में भाजपा 7 से 8 हजार में हारी। कोई भी सफलता हमे एक प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। असफलता एक चुनौती होती है। 2027 में एक बार फिर यूपी में कमल खिलेगा।

आरोपों के बावजूद अदाणी की मदद कर रहा सौर ऊर्जा निगमः कांग्रेस

नई दिल्ली,(एजेंसी)। रमेश ने कहा कि श्अदाणी सात महीने की देरी से तय वादे के मुकाबले एक तिहाई बिजली की ही आपूर्ति करेंगे, लेकिन भारत के सौर ऊर्जा निगम ने इस दौरान बिजली को 40 फीसदी ज्यादा दरों पर बिजली एक्सचेंज को बेचने की अनुमति दे दी है। इसका नतीजा ये है कि आंध्र को कोई बिजली नहीं मिलेगी और अदाणी ग्रीन को फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत का सौर ऊर्जा निगम उद्योगपति गौतम अदाणी का पक्ष ले रहा है। कांग्रेस ने कहा कि अदाणी के खिलाफ अमेरिका में गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में समय पर बिजली आपूर्ति न कर पाने के बावजूद भी अदाणी ग्रीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसके लिए केंद्र पर तंज कसते हुए धन्यवाद कहा। जयराम रमेश ने अदाणी ग्रीन पर लगाए आरोप जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि श्अदाणी ग्रीन कंपनी ने अनुबंध के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार को तीन गीगावाट्स बिजली की सप्लाई करने का वादा किया था, लेकिन अनुबंध पाने के लिए 1400 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के बावजूद ग्रीन अदाणी कंपनी ने राज्य को एक यूनिट बिजली की भी आपूर्ति नहीं की है, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि इसके बावजूद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद।

हिंसा पर जारी जुबानी जंग

● संभल पर जमकर हो रही सियासत, एक-दूसरे पर कैसे वार-पलटवार कर रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष?

नई दिल्ली,(एजेंसी)।एक ओर जहां संभल शाही जामा मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो वहीं दूसरी ओर सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर राजनीति भी जारी है। रविवार को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी। आइये ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि संभल मामले पर कैसे बयानबाजी जारी है... उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। बीते रविवार को जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिल वाद के आधार पर किए गए सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई और कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग घायल हुए। शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में शुक्रवार को पहली सुनवाई है। उधर मस्जिद का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। शुक्रवार को संभल मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे। संभल मसले पर राजनीति भी हावी रही। जहां सर्वे के दौरान हुई हिंसा को विपक्षी दलों ने सरकार की नाकामी बताई तो वहीं सरकार ने कहा है कि सर्वे का आदेश अदालत का है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया। आइये ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि संभल मामले पर राजनीति क्या हो रही है? किस नेता ने क्या बयान दिया है? सरकार क्या कह रही है? पहले जानते हैं कि संभल में क्या हुआ है? दरअसल, 19 नवंबर को एक स्थानीय अदालत ने संभल के चंदौसी स्थित जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। यह आदेश चंदौसी में संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत ने पारित किया था। सर्वे का आदेश एक याचिका के बाद आया था जिसमें दावा किया गया था कि 1529 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। याचिका 19 नवंबर को ही दायर की गई थी और उसी दिन न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और उसे मस्जिद में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट 29 नवंबर तक उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए। 19 नवंबर को ही स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में एक सर्वे किया गया था। वहीं रविवार (24 नवंबर) को टीम जब सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दोबारा मस्जिद पहुंची तो संभल में बवाल हो गया।

संसदीय व्यवधान तरीका नहीं एक बीमारी, सदन में विपक्ष के गतिरोध पर बोले धनखड़

नई दिल्ली,(एजेंसी)। सदन में बढ़ते व्यवधान को देखते हुए धनखड़ ने कहा संसदीय व्यवधान एक उपाय नहीं, बल्कि बीमारी है। यह हमारी नींव को कमजोर करता है और संसद को अप्रासंगिक बना सकता है। हमें अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी चाहिए। अडानी मामले, मणिपुर की स्थिति और संभल हिंसा पर चर्चा की विपक्ष की मांग के बीच संसद में हो रहे व्यवधान पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि संसद में व्यवधान एक तरीका नहीं बल्कि एक बीमारी है। उन्होंने सदस्यों से ष्पारंपरिक विचारशील चर्चाष में शामिल होने और सार्थक संवाद की भावना अपनाने का आग्रह किया। संसदीय व्यवधान उपाय नहीं बीमारी– धनखड़ धनखड़ ने कहा संसदीय व्यवधान एक उपाय नहीं, बल्कि बीमारी है। यह हमारी नींव को कमजोर करता है और संसद को अप्रासंगिक बना सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी चाहिए। अगर संसद अपने कर्तव्यों से भटकती है, तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि 26 नवंबर को 75वें राष्ट्रीय संविधान दिवस पर संसद के पास 1.4 अरब लोगों को आशा का संदेश भेजने का अवसर था, लेकिन इस ऐतिहासिक अवसर को हम खो चुके हैं। शनियमों का उल्लघन सदन को अपवित्र करने जैसाश धनखड़ ने कहा अगर हम अपने मन मुताबिक या किसी भी तरीके से काम करने लगते हैं।

संभल मामला: हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे: सुप्रीम कोर्ट

● मस्जिद समिति ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली,(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम निर्देश दिए, जिनके मुताबिक निचली अदालत को इस मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले से उन्हें कुछ आपत्तियां हैं। संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है और कहा कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। मस्जिद समिति ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दरअसल मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वह उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। पीठ ने कहा कि यह मामला उचित मंच पर उठाया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम निर्देश दिए, जिनके मुताबिक निचली अदालत को इस मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले से उन्हें कुछ आपत्तियां हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय से याचिका दायर होने के बाद तीन दिनों में याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश गौरतलब है कि निचली अदालत के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर द्वारा संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। इस सर्वे के दौरान ही बीते दिनों संभल में हिंसा भड़की, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालात को देखते हुए एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और जारी न करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को हिदायत दी है कि शांति और सद्भाव का माहौल कायम रखा जाए।

अदालत ने प्रशासन से शांति समिति गठित कर सद्भाव कायम करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने जताई नाराजगी कोर्ट ने कहा कि जिस जल्दबाजी में मामले पर ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई।

दिग्विजय सिंह ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, एसएसए की राशि आवंटित करने का आग्रह

भोपाल, नयी दिल्ली,(एजेंसी)। संसद की शिक्षा, बाल, युवा मामले एवं खेल सम्बन्धी स्थायी समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत राज्यों को आवंटित की जाने वाली धनराशि जारी करने में देरी के मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री सिंह के कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि तमिलनाडु, केरल एवं पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने एसएसए के तहत केंद्रीय निधि के अपने हिस्से को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण देरी की सूचना दी है, जिससे शिक्षा प्रणाली में असमानताओं को दूर करने के प्रयासों को पटरी से उतरने का जोखिम है। राज्यसभा सांसद श्री सिंह ने आग्रह किया है कि शिक्षा मंत्री श्री प्रधान इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान दें और राज्यों को समय पर धनराशि जारी करने को सुनिश्चित करें। उन्होंने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करें और राज्यों को योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाएं। पत्र में श्री सिंह ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि कई राज्यों ने एसएसए के तहत केंद्रीय निधि के अपने हिस्से को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण देरी की सूचना दी है, विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने अभी तक अपना हिस्सा प्राप्त नहीं किया है। इस वजह से बुनियादी ढांचे के निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य आवश्यक हस्तक्षेपों सहित महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। राशि आवंटन की इस तरह की देरी न केवल प्रगति में बाधा डालती है बल्कि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने वाले हितधारकों को भी हतोत्साहित करती है।

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली,(एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती कथित घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता कुंतल घोष को शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उन्हें यह राहत दी। पीठ जमानत देने के साथ ही यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता फिलहाल कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाल सकता। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि इस साल जनवरी में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, लेकिन सीबीआई द्वारा पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव होने के कारण इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। पीठ ने कहा " निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।" याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें 20 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज धन शोधन से संबंधित मामले में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि याचिकाकर्ता एक व्यापक घोटाले और गहरी साजिश का हिस्सा था। उसने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की मूल वेबसाइट जैसी एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी। एजेंसी की ओर से दावा किया कि अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए उनसे चार करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई। यह भी तर्क दिया गया कि घोष पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए और एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उसकी रिहाई के बाद गवाहों को डराया–धमकाया जा सकता है हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। निलंबित टीएमसी नेता घोष को पहली बार ईडी ने 21 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि घोष ने प्रत्येक नौकरी चाहने वाले से 20 लाख रुपये एकत्र किए और अपने नाम के दो बैंक खातों में 6.5 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए। उनमें एक आईसीआईसीआई बैंक में और दूसरा इंडसलैंड बैंक है। इसके बाद निवेश के उद्देश्य से उक्त राशि को तुरंत अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। ईडी ने यह भी दावा किया कि घोष ने मनोरंजन उद्योग में कदम रखा।

और संगीत वीडियो और लघु फिल्में बनाने के लिए एक साझेदारी फर्म बनाई। एकत्रित धन का उपयोग टॉलीवुड सितारों के लिए महंगे वाहन खरीदने में किया गया।

सम्पादकीय.....

प्रियंका का डंका

केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा की 4.1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हुई भारी जीत कांग्रेस पार्टी के लिये एक उत्साहजनक संदेश है। निश्चित रूप से उनके राजनीतिक जीवन और कांग्रेस पार्टी के लिये यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। शायद यह पहली बार है कि संसद में गांधी परिवार के तीन लोग सदस्य हैं। उनसे पहले राज्यसभा में मां सोनिया गांधी और लोकसभा में भाई राहुल गांधी की सक्रिय उपस्थिति बनी हुई है। उनकी इस जीत से निश्चित रूप से संसद में गांधी परिवार के प्रभाव को मजबूती मिलेगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह आज भी वंशवादी नेतृत्व पर पार्टी की निर्भरता को रेखांकित करता है। निस्संदेह, प्रियंका गांधी अपने आकर्षक व्यक्तित्व व प्रभावी कुशल वक्ता के रूप में पहचान रखती हैं। वह कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य की बड़ी उम्मीद हैं। उनकी उपस्थिति पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करती है। एक ओर जहां राहुल गांधी के नेतृत्व व अभिव्यक्ति को लेकर आलोचना की जाती रही है, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने नपे–तुले शब्दों में मुद्दों को तार्किक ढंग से उठाने के लिये भी जानी जाती हैं। उनका यह राजनीतिक कौशल वायनाड में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बखूबी देखा गया। अपने इसी गुण के चलते वह चुनाव अभियान के दौरान तमाम मतदाताओं, खासकर महिलाओं के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में कामयाब रहीं। लोगों को साथ जोड़ने की यही क्षमता उनकी निर्णायक जीत में खासी मददगार साबित भी हुई। उनके चुनाव अभियान ने कार्यकर्ताओं में नये उत्साह का संचार किया। यही वजह है कि पार्टी के भीतर उनकी सफलता को लेकर खासा जोश भी है। पार्टी के भीतर भी कई लोगों को उम्मीद है कि उनकी इस रिकॉर्ड जीत से कांग्रेस पार्टी संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो सकेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो देश में पार्टी की अपील में आशातीत विस्तार की संभावनाओं को बल मिल सकेगा। फलतः पार्टी को मौजूदा संकट से उबरने में मदद मिलेगी। यह निर्विवाद सत्य है कि राजनीतिक समय की दृष्टि से प्रियंका गांधी वाड्रा की सफलता के खास मायने हैं। उनकी संसद में दस्तक ऐसे समय में हुई जब देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रही है। पार्टी को हाल के दिनों में महत्वपूर्ण चुनावी झटकों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में सत्ता की चाबी पार्टी के हाथ से फिसलकर भाजपा की झोली में जा गिरी है। राजनीतिक पंडित इन असफलताओं को पार्टी की घटती प्रासंगिकता के रूप में देखते रहे हैं। साथ ही कहा जाता है कि पार्टी भाजपा की संगठनात्मक ताकत को चुनौती दे पाने में विफल रही है। दूसरे शब्दों में, पार्टी भाजपा के राजनीतिक विमर्श का विकल्प नहीं दे पा रही है। साथ ही यह अहम सवाल भी उठाया जा रहा है कि सक्रिय राजनीति में प्रियंका का उदय क्या संघर्षरत कांग्रेस में नई जान फूंक सकने में कामयाब होगा? दरअसल, वायनाड में उनकी जीत को स्थानीय सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर दमदार उपस्थिति के लिये उन्हें अभी और मेहनत करनी होगी। इस जीत को राष्ट्रीय गति में बदलने के लिये रणनीतिक सुधारों, गठबंधनों और भविष्य के लिये स्पष्ट दृष्टिकोण की जरूरत होगी। अभी यह देखना बाकी है कि क्या भविष्य के लिये वे एक स्पष्ट दृष्टिकोण का लाभ पार्टी का जनाधार विकसित करने के लिये दे पाएंगी। या फिर वह कांग्रेस की वंशवादी राजनीति की निरंतरता के रूप में उभरती हैं। निस्संदेह, जैसे ही वह राष्ट्रीय सुर्खियों में कदम रखेंगी, उन्हें पार्टी में नई प्राणवायु का संचार करने के लिये कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें कालांतर यह भी साबित करना होगा कि कांग्रेस मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एक व्यवहार्य विकल्प पेश कर सकती है। बहरहाल, प्रियंका गांधी वाड्रा की वायनाड में हुई शानदार जीत से न केवल केरल बल्कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई आशा का संचार हुआ है।

भारत–बांग्लादेश रिश्तों में एक और पेच पडने का अंदेशा

मोहम्मद युनूस ने शेख हसीना को प्रत्यर्पित कराने का इरादा जताया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने के बाद से युनूस की अंतरिम सरकार ने पहले भी कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिन्हें भारत के हित में नहीं माना जा सकता। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार (जिनके हाथ में वास्तविक सत्ता है) मोहम्मद युनूस की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित कराने की ताजा घोषणा से भारत–बांग्लादेश रिश्तों में एक और पेच पडने का अंदेशा है। युनूस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि उनकी सरकार भारत से हसीना को वापस भेजने को कहेगी, ताकि जुलाई–अगस्त के छात्र आंदोलन में हुई मौतों के लिए उनकी जवाबदेही तय की जा सके। बांग्लादेश यह मांग औपचारिक रूप से सामने रखता है, तो भारत के लिए एक बड़ा असमंजस पैदा होगा। वैसे भी बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने के बाद से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्हें भारत के हित में नहीं माना जा सकता। अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान का एक मालवाहक पोत कराची से चल कर बांग्लादेश के दक्षिणपूर्वी तट पर स्थित चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के बाद से दोनों देशों में पहली बार सीधा समुद्री संपर्क हुआ है। इससे पहले दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार सिंगापुर या कोलंबो के जरिए होता था। खुद बांग्लादेश ने इस घटना को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में महत्त्वपूर्ण कदम की शुरुआत बताया है। कहा है कि इस रूट पर समुद्री संपर्क बनना दोनों देश के बीच सप्लाई चेन को आसान बनाएगा, परिवहन के समय में कमी आएगी और आपसी व्यवसाय के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे। यह निर्विवाद है कि यह सीधा समुद्री संपर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के राजनयिक रिश्तों में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। इसके पहले खबर आई थी कि दोनों देश एक परमाणु सहयोग समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत पाकिस्तान परमाणु बिजली संयंत्र लगाने में बांग्लादेश की मदद करेगा। स्पष्टतरू युनूस की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से रिश्तों में गर्माहट लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का पहलू है।

संभल हिंसा से सुलगते सवालों का जवाब आखिर कौन देगा?

कमलेश पांडे

उल्लेखनीय है कि संभल के कैला देवी मंदिर के ऋषिराज गिरी समेत आठ वादियों ने सिविल जज सीनियर डिविजन आदित्य कुमार सिंह की चंदौसी स्थित कोर्ट में इस बाबत एक वाद दाखिल किया है। जिसके दृष्टिगत कोर्ट ने कमिशन गठित कर रिपोर्ट मांगी है। कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। भारत देश और भारतीय इसका जीता–जागता उदाहरण हैं। मुहम्मद बिन कासिम जैसे मुस्लिम आक्रांताओं और उनके अनुगामियों ने तलवार की नोंक पर भारत की देशज सत्ता हथियाने के बाद यहां की सनातन सभ्यता–संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका हिसाब–किताब अब उनकी धर्मांतरित पीढ़ियों को देना पड़ रहा है। खासकर मंदिरों को ढहाकर जिन मस्जिदों का निर्माण किया गया, उनकी मुक्ति यानी जीर्णोद्धार का अभियान अब स्थानीय प्रशासन के गले की हड्डी बन चुकी है।

देखा जाए तो ऐसे मामलों में कभी आपसी विवाद, तो कभी न्यायिक आदेश के अनुपालन में सिविल व पुलिस प्रशासन को अपनी सक्रियता दिखानी पड़ती है, लेकिन कानून का राज स्थापित करने में उनकी विफलता से जब तब सांप्रदायिक दंगे भी भड़क जाते हैं जिससे धन–जन की भारी क्षति भी होती है। अतीत की बात यदि भुला दी जाए तो भी स्वतंत्र भारत की यह एक बड़ी चुनौती है, जबकि यह हिंदुओं के हिस्से का हिंदुस्तान है, क्योंकि मुस्लिमों को तो पाकिस्तान दे ही दिया गया, जिसका भाग ही बंगलादेश है। लेकिन भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के बजाय धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करना, फिर वोट बैंक की राजनीति के तहत मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाना और आतंकवाद पर समझौतापरस्त रुख अपनाने की प्रतिक्रियाओं में उभरे राष्ट्रवाद व हिंदुत्व की जनभावना ने जब बदले की कार्रवाई शुरू की तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों में खलबली मच गई। रामजन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद और उसके न्यायसंगत समाधान ने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं के सत्ता की चूलें हिला दीं और हर ओर उनका पतन हुआ। अब रामजन्मभूमि मुक्ति मिशन के पूरा होने के बाद न केवल मथुरा–काशी, बल्कि वैसे तमाम मंदिरों की मुक्ति के सवाल जनमानस में सुलगने लगे हैं, जिन्हें बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया था। चूंकि इतिहास खुद को दुहराता है, इसलिए अब धीरे–धीरे पुराने गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं, उखाड़े जाने लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश के संभल जनपद के सदर तहसील स्थित दीपा सराय की जामा मस्जिद को जब हिंदू पक्ष श्री हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और उनके इसी दावे के आधार पर कोर्ट ने जब मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, तो फिर कानून के अनुपालन में कार्य कर रहे लोगों के विरुद्ध शांतिप्रिय समुदाय द्वारा बवाल काटने को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि संभल के कैला देवी मंदिर के ऋषिराज गिरी समेत आठ वादियों ने सिविल जज सीनियर डिविजन आदित्य कुमार सिंह की चंदौसी स्थित कोर्ट में इस बाबत एक वाद दाखिल किया है। जिसके दृष्टिगत कोर्ट ने कमिशन गठित कर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर 2024 को होगी। हिंदू पक्ष के एक स्थानीय वकील गोपाल शर्मा ने बताया है कि, कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि बाबरनामा और आइन– ए–अकबरी ने पुष्टि की है कि उस स्थान पर हरिहर मंदिर था। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। लिहाजा इस मामले में उन्होंने कोर्ट में बाबरनामा और आइन–ए–अकबरी का संदर्भ दिया है, जिनसे साफ होता है कि वहां हरिहर मंदिर था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगलकाल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।

लिहाजा, महंत ऋषि राज गिरि महाराज आदि ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी। इस मामले में सिविल जज के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन मुख्य याचिकाकर्ता हैं। चूंकि चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की अदालत में वाद दाखिल किया था। इसलिए कोर्ट ने इसी याचिका पर 7 दिन में सर्वे रिपोर्ट मांगी है, जिसे 29 नवंबर को जमा करना है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव के नेतृत्व में टीम ने 19 नवंबर की शाम को ही सर्वे की शुरुआत कर दी थी। रविवार को टीम सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दोबारा मस्जिद पहुंची थी।

मसलन, कोर्ट से सर्वेक्षण का आदेश जारी होने के बाद मंगलवार को जब पहली बार सर्वे हुआ, तब से ही मुस्लिम समुदाय में असंतोष फैलने लगा और उस दिन भी विरोध हुआ था। क्योंकि मुस्लिम पक्ष मान रहा है कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई, उनको पर्याप्त समय या अवसर नहीं दिया गया। इसलिए सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में शांतिप्रिय समुदाय के लोग एकत्रित हो गए, जिससे स्थिति पहले तनावपूर्ण हुई, फिर अनियंत्रित हो गई। जिसे भारी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया गया।

बताया जाता है कि मस्जिद में आमतौर पर रविवार दोपहर में नमाज होती है। ऐसे में सर्वे करने वाली टीम को इससे पहले आने के लिए कहा गया था। सर्वे टीम के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुबह साढ़े 7 बजे टीम पहुंची और 10 बजे तक सर्वे चला। फिर हम जरूरी तस्वीरें और विडियो लेकर जब निकलने लगे तभी भीड़ ने घेर लिया। फिर सर्वेक्षण टीम को सुरक्षित निकालने के क्रम में जो कुछ हुआ, वह न केवल योगी सरकार बल्कि शांतिप्रिय समुदाय के लिए भी एक कलंक है।

ऐसा इसलिए कि लखनऊ में बाजाप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि, ष्संभल में एक गंभीर घटना हुई। चुनाव के बारे में चर्चा को बाधित करने के लिए सुबह जानबूझकर एक सर्वेक्षण टीम भेजी गई थी। इसका उद्देश्य अराजकता पैदा करना था, ताकि चुनावी मुद्दों पर कोई बहस न हो सके। मैं कानूनी या प्रक्रियात्मक पहलुओं में नहीं जाना चाहता, लेकिन दूसरे पक्ष की बात भी नहीं सुनी गई। यह जानबूझकर भावनाओं को भड़काने और चुनाव में धांधली पर चर्चा से बचने के लिए किया गया था। संभल में जो कुछ हुआ, वह चुनावी गड़बड़ियों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी, सरकार और प्रशासन की ओर से किया गया था।ष

हालांकि, सवाल यह भी है कि एक न्यायिक और प्रशासनिक कार्रवाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सियासी रंग क्यों दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग उनका वोट बैंक है? आखिर वह इस बात से अनजान क्यों हैं कि संभल जिला प्रशासन ने शनिवार को ही शांति भंग की आशंका में जिन 34 लोगों को 10 लाख रुपये तक के मुचलके पर पाबंद किया, उसमें सपा के संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क भी शामिल हैं। वहीं, इस मुचलके पाबंदी के ठीक एक दिन बाद वहां जिस तरह से आगजनी व फायरिंग की गई, जिसमें कुछ लोग हताहत भी हुए, उससे तो यही पता चलता है कि सर्वेक्षण टीम व पुलिस पर हमलावरों को सियासी संरक्षण प्राप्त है। तभी तो संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने एक अधिसूचना जारी कर किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को अधिकारियों के आदेश के बिना संभल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है।

बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिल वाद के आधार पर सर्वे के लिए रविवार सुबह सात बजे कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची तो संभल में बवाल हो गया। अचानक टीम के पहुंचने की सूचना पर जुटी भीड़ मस्जिद में दाखिल होने कोशिश करने लगी। फिर उन्हें रोकने पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हिंसक हुई भीड़ ने चंदौसी के सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बवाल में घिरकर दो–तीन लोगों की मौत हो गई। कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए संभल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि सर्वे टीम कोर्ट कमिश्नर चंदौसी के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह राघव की अगुवाई में आई थी। संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई भी टीम के साथ थे। इसलिए बाहर हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठियां चलाकर सर्वे टीम को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। भले ही पुलिस के आक्रमक होते ही उपद्रवी भागने लगे, लेकिन कुछ देर बाद भीड़ फिर जुट गई और लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान छतों से फायरिंग होने लगी। मौके पर पहुंची अन्य जिलों की पुलिस और पीएसी के साथ अधिकारियों ने उपद्रव करती भीड़ से मोर्चा लिया। इसके बावजूद करीब डेढ़ घंटे हालात बेकाबू रहे। जैसे–तैसे भीड़ को तितर–बितर कर पुलिस आगे बढ़ी। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी।

इस घटना के बाद पूरे शहर में तनाव गहरा गया। शाम होने तक सख्ती इतनी बढ़ा दी गई कि शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। एक ओर हिंसा का शिकार युवकों के परिजनों ने पुलिस की गोली से मौत होने की बात कही है। वहीं, दूसरी ओर मौके पर पहुंचे कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि तीन युवकों में दो की मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठी का प्रयोग किया था। तीसरे युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। घायलों में डीआईजी, संभल के डीएम, एसपी और एसडीएम भी शामिल हैं।

वहीं, संभल बवाल में हयातनगर निवासी रोमान (40), फत्तेहउल्ला सराय निवासी बिलाल (22) और मोहल्ला कोट तबेला निवासी नईम (35) की मृत्यु हो गई। वहीं, एक अन्य मृतक की पहचान नहीं हुई है। इस बवाल के बाद पुलिस के साथ पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ को शहर में लगाया गया है। बवाल में कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए हैं। सभी का मेडिकल कराया गया है। बवालियों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, उपद्रवी गिरफ्तारी के डर से चोरी–छिपे इलाज करवा रहे हैं। घायल लोग कहां और कैसे इलाज करा रहे हैं, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। एएसपी श्रीशचंद्र के मुताबिक, दो घायल ही मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंचे थे। जो लोग चोरी–छिपे इलाज करा रहे हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। पथराव–फायरिंग में पुलिस ही नहीं, सैकड़ों उपद्रवी भी घायल हुए हैं। सवाल है कि जब पिछले पांच दिनों से संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर विवाद चल रहा था, नेता बयानबाजी भी कर रहे थे, पुलिस लोगों को मुचलकों में पाबंद भी कर रही थी, लेकिन बवाल को भांपने में अधिकारी नहीं बल्कि जिले से लेकर मंडल मुख्यालय तक का सूचना तंत्र भी फेल हो गया। रविवार जैसे बवाल का कोई इनपुट नहीं मिला था। वहीं, करीब डेढ़ घंटे तक चले पथराव में गलियां ईंट–पत्थरों से पट गईं। हालात नियंत्रित होने के बाद पुलिस ने नगर पालिका की टीम बुलवाई और गलियों से ईंट–पत्थर हटवाने के साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटवाकर थाने भिजवाया। तब जाकर जामा मस्जिद के आसपास की सड़कें साफ हुईं। हैरत की बात है कि पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवी नकाब पहने हुए थे। पुलिस की बार–बार चेतावनी के बाद भी न तो पथराव बंद किया और न ही पीछे हटे। पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले छोड़े तो उपद्रवियों ने वही गोले उठाकर पुलिस पर फेंक दिए। इससे पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालने में परेशानी हुई। इसलिए पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि उपद्रव करने वाले पेशेवर थे और वह हिंसा करने ही आए थे।

इससे साफ है कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में जनहानि के साथ बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। इसलिए बवाल के बाद पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने के प्रयास में जुटी है। सीसीटीवी से पहचान करने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ने के प्रयास में जुटी है। पुलिस ऐसे लोगों का सहयोग ले रही है, जो शांतिप्रिय हैं। घर–घर पुलिस की टीम दबिश दे रही है और उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस अधिकारियों की मानें, तो रविवार शाम तक दो महिलाओं समेत 21 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। वहीं, हिरासत में ली गईं दोनों महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि पुलिस को टारगेट कर पथराव किया गया। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ बाहरी लोगों ने भीड़ में शामिल होकर उपद्रव किया है। पत्थर फेंकने और तोड़फोड़ व पथराव करने वाले अधिकांश उपद्रवियों के चेहरे रुमाल से ढके हुए थे। जिससे पता चलता है कि यह योगी सरकार के खिलाफ कोई सोची समझी सियासी साजिश है। इसलिए पुलिस अब क्षेत्र में गश्त कर घर–घर उपद्रवियों की तलाश कर रही है।

संभल में जो कुछ हुआ, वह लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। यह सांप्रदायिक दंगा कम और पुलिस के विरुद्ध हिंसा की कार्रवाई ज्यादा प्रतीत हुई, जो एक खतरनाक ट्रेंड है। बहरहाल, पूरे देश में इस मनोवृत्ति को प्रशासन को कुचलना ही होगा, ताकि सर्वत्र शांति बहाल रहे। उसे ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करनी होगी, ताकि पुलिस की जरूरत ही कम पड़े। यदि भारत वाकई धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर धर्म आधारित शिक्षा के प्रशासनिक स्वीकृति और सरकारी पाठ्यक्रम दोनों पर रोक लगे। यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो।

उदास लोगों का देश बनना भारत की एक त्रासदी

ललित गर्ग

भारत के मानव–स्वभाव में उग्र हो रही उदासी एवं निराशा का बड़ा कारण प्रदूषित हवा एवं पर्यावरण है। शुद्ध वायु में ही जीवन है और उसी में जीवन की सकारात्मकता एवं जीवन–ऊर्जा समाहित है। यही हमारी अराजक जीवन शैली को संयमित कर सकती है। भारत उदास, निराश एवं थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। हम प्रसन्न समाजों की सूची में अव्वल नहीं आ पा रहे हैं। आज अक्सर लोग थके हुए, उदास, निराश नजर आते हैं, बहुत से लोग हैं जो रोजमर्रा के काम करने में ही थक जाते हैं। उनका कुछ करने का ही मन नहीं होता। छोटे–मोटे काम भी थकाऊ और उबाऊ लगते हैं। विडम्बना तो यह है कि लम्बे विश्राम एवं लम्बी छुट्टियों के बाद भी हम खुद को तरोताजा नहीं बना पा रहे हैं। भारत में ऐसे लोगों का प्रतिशत लगभग 48 तक पहुंच गया है, जो चिन्ता का बड़ा सबब है। ऐसे थके एवं निराश लोगों के बल पर हम कैसे विकसित भारत एवं नये भारत का सपना साकार कर पायेंगे? यह सवाल सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को आत्ममंथन करने का अवसर दे रहा है, वहीं नीति–निर्माताओं को भी सोचना होगा कि कहां समाज निर्माण में त्रुटि हो रही है कि हम लगातार थके हुए लोगों के देश के रूप में पहचाने जा रहे है। खुशहाल देशों की सूची में भी हम सम्मानजनक स्थान नहीं बना पा रहे हैं। हर साल जारी होने वाली वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट, जो संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की प्रस्तुति है, बताती है कि कौन देश सबसे ज्यादा खुश और कौन से देश सबसे ज्यादा दुखी हैं? वैश्विक स्तर पर खुशी का स्तर तय करने के कई पैमाने है, जिनमें लोगों की आजादी, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, आय जैसी बातें शामिल होती हैं। सबसे अधिक दुखी देशों की लिस्ट में पहला नाम अफगानिस्तान का आता है। इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग भी बेहद निराश करने वाली है। भारत में उदास एवं निराश लोगों की स्थिति के कई कारण हो सकते हैं–जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होना, कृषि पर ज्यादा निर्भरता, आर्थिक विकास की दर कम होना, बेरोजगारी, अशिक्षा, आय में असमानता, भ्रष्टाचार, आंतरिक द्वेष, कमजोर आर्थिक नीतियां एवं जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया। दुःख जीवन के उतार–चढ़ाव का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह इंसान खुशी, निराशा, उदासी, गुस्सा, गर्व आदि भावनाओं को महसूस करता है, उसी तरह हर कोई समय–समय पर दुःख महसूस करता है। दुःख कभी–कभी इंसान को मोटीवेट करने में भी मदद कर सकता है, लेकिन यह जिजीविषा, खुशहाली, सक्रियता, जोश को भी कम करता है। दुनिया की खुशहाल देशों की सूची में भारत इस वर्ष 143 देशों में 126वें स्थान पर है। यह रैंक पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल वही रही है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन 60वें, नेपाल 93वें, पाकिस्तान 108वें, म्यांमार 118वें, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है।

भारत दुनिया का सबसे उदास देश है। शोधों के निष्कर्ष बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन एवं अत्यधिक गर्मी के कारण 2100 तक भारत में हर साल 15 लाख लोगों की मौत हो सकती है? इसी कारण उदास लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत सबसे अधिक अवसादग्रस्त देशों की सूची में सबसे ऊपर है। भले ही भारतीयों को स्वभाव से समायोजित और संतुष्ट लोगों के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह पता चला है कि वे सबसे अधिक उदास भी हैं। एक तरफ हम खुद को किसी भी चीज में आसानी से समायोजित कर लेते हैं, चाहे वह कम पैसा हो, खराब सड़कें हों, बुनियादी ढाँचे की कमी हो या कुछ भी हो। नेशनल केयर ऑफ मेडिकल हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार लगभग 6.5 प्रतिशत भारतीय गंभीर मानसिक स्थितियों से पीड़ित हैं, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी। सरकार जागरूकता कार्यक्रम चला रही है लेकिन मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टरों की भी कमी है।

भारत के मानव–स्वभाव में उग्र हो रही उदासी एवं निराशा का बड़ा कारण प्रदूषित हवा एवं पर्यावरण है। शुद्ध वायु में ही जीवन है और उसी में जीवन की सकारात्मकता एवं जीवन–ऊर्जा समाहित है। यही हमारी अराजक जीवन शैली को संयमित कर सकती है। कुछ ऐसे रोग जो उपचार योग्य नहीं माने जाते, उन पर अंकुश लगा सकती है। व्यक्ति अपने घर में आहार–विहार को संतुलित करके भी उत्साही एवं प्रसन्न होने का प्रयास कर सकता है। हम सूरज के उगने से पहले उठें। धूप में न बैठने से हम विटामिन डी की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे शरीर में उदासी एवं निराशा बढ़ जाती हैं। आमतौर पर विदेशों में लोग नवंबर से जनवरी तक सूर्य स्नान लेते हैं जिससे लोगों को विटामिन–डी मिल जाता है। आज आम लोग शारीरिक श्रम नहीं करते। खान–पान की चीजों में भारी मिलावट है। बाजार की शक्तियां कई तरह के भ्रम फैलाती हैं।

पारिवारिक जीवन अनेक दबावों से घिरा है, कॉरपोरेट संस्कृति में रिश्ते, स्वास्थ्य एवं खुशहाली बहुत पीछे छूट रही है। वास्तव में अधिकांश आधुनिक रोग काम न करने की बीमारी है। हम लोग दिमाग को थका रहे हैं, शरीर को नहीं थका रहे हैं। इसी वजह से शरीर कोष्भुगतना पड़ रहा है। आदमी पैदल नहीं चल रहा है। स्वस्थ रहने के लिये जरूरी है हम आहार सही ढंग से लें। दरअसल हमारा आहार दवा है। देर रात भोजन करना, देर रात तक जगना एवं सुबह देर से उठना शरीर के साथ अत्याचार करने जैसा है। इन्हीं जटिल से जटिलतर होती स्थितियों ने हमें उदासी दी है। वैसे उदासी, निराशा, थकावट, दुख या खुशी एक ऐसी अवस्था है, जिस पर किसी सर्वे के जरिये एकमत नहीं हुआ जा सकता। फिर भी, ऐसी सूचियों से सकारात्मक प्रेरणा लेते हुए प्रसन्न, उत्साही, सक्रिय समाज की संरचना के लिये तमाम तरह के प्रयास करने में ही भलाई है। हमारा शीर्ष नेतृत्व आजादी के बाद से ही निरन्तर आदर्शवाद और अच्छाई का झूठ रचते हुए सच्चे आदर्शवाद के प्रकट होने की असंभव कामना करता रहा है, इसी से जीवन की समस्याएं सघन होती गयी है, इसी ने उदासी को बढ़ाया है, नकारात्मकता का व्यूह मजबूत होता गया है, खुशी, उत्साही, जोशीला एवं प्रसन्न जीवन का लक्ष्य अधूरा ही रहा है, इनसे बाहर निकलना असंभव–सा होता जा रहा है। दूषित और दमघोंटू वातावरण में आदमी अपने आपको टूटा–टूटा सा अनुभव कर रहा है। आर्थिक असंतुलन, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार उसकी धमनियों में कुत्सित विचारों का रक्त संचरित कर रहा है। ऐसे जटिल हालातों में इंसान कैसे खुशहाल, जोशीला एवं सकारात्मक जीवन जी सकता है?

अमृत कलश टाइम्स
हिन्दी दैनिक

संक्षिप्त समाचार

नाबालिग के साथ दुष्कर्म, डीजे संचालक ने वारदात को दिया अंजाम

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज में डीजे

संचालक ने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग शादी समारोह में शामिल होने गई थी। उसका कहना है कि डीजे संचालक टॉयलेट में ले जाकर रेप किया है। घटना देर रात करीब 2 बजे की है। इंस्पेक्टर गोसाईगंज बृजेश त्रिपाठी का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर थ्प्त दर्ज की गई है। आरोपी को हिरासत मे लेकर कार्रवाई की जा रही है।

कैंसर पीड़िता का अधिकारियों ने भरा टैक्स,नगर निगम समाधान दिवस में पहुंची थी पीड़िता

लखनऊ (यूएनएस)। लखनऊ नगर निगम में शुक्रवार को समाधान दिवस पर 48 आपत्तियों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर जोन 5 से विमलेश का कुल टैक्स 24940 था। विमलेश ने बताया कि वह कैंसर पीडित है इसलिए टैक्स भरने में सक्षम नहीं है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ब्याज माफ करते हुए मूल राशि अधिकारियों ने मिलकर जमा कर दिया। समाधान दिवस में महापौर सुषमा खर्कवाल उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि लखनऊ वासियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज कुल 48 आपत्ती आई जिसमें सभी का निस्तारण कर दिया गया। पहले की तुलना में लगातार आपत्तियों की संख्या कम हो रही है। सभी जोन के आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त कोई निर्देश दिया गया है कि हर महीने के पहले शुक्रवार को नगर निगम में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। पहले शुक्रवार को समाधान दिवस पर संबंधित तमाम अधिकारी उपलब्ध होंगे मौके पर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। सुषमा खर्कवाल ने बताया कि जोन 5 से आई विमलेश नाम की कैंसर पीडित घरों में काम करती है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय। आज तक उसने टैक्स नहीं जमा किया था जो लगभग 25000 हो गया था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने सराहनीय कार्य करते हुए उसके ब्याज को माफ करके टैक्स स्वयं जमा कर दिया। पीड़िता के इलाज में भी हम लोग हर संभव मदद करेंगे। सराहनीय कार्य के लिए सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। समाधान दिवस में जोन 5 से आए रूप नारायण तिवारी ने बताया कि। विगत 6 वर्षों से टैक्स समायोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2018 में टैक्स ज्यादा जमा हो गया था जिसका निस्तारण नहीं हुआ। 2022 में नगर निगम के द्वारा शासन में रिपोर्ट सौंप दी गई की समस्या का समाधान हो गया जबकि हुआ नहीं था। अब 2024 में निगम ने इसे स्वीकार किया है। हमारी मांग है कि जो 25 हजार अधिक राशि जमा कर दिया था उसका समायोजन हो , या फिर हमें वापस किया जाए।

तिलक समारोह में बवाल करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ (यूएनएस)। तिलक समारोह में बवाल करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी दिलीप चौरसिया के बेटे प्रांशू के तिलक समारोह में डीजे पर डांस के दौरान अभद्रता और विवाद किए थे।समारोह में जब इनको टोका गया तो गुस्से में आकर अपने साथियों को फोन कर दिया। कुछ देर बाद 12 से 15 लोग बाइक से पहुंचे। रिश्तेदारों की जमकर पिटाई कर दी। दो वाहनों में भी तोड़फोड़ की। पीड़ित दिलीप चौरसिया की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार को मुख्य आरोपी रोहित (निवासी बैरीसालपुर) और शिवसागर (निवासी शेरपुर लवल, थाना निगोहां) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जयपुरिया स्कूल के टीचर ने किया सुसाइड

लखनऊ (यूएनएस)। गोमतीनगर के विशालखंड में रहने वाले जयपुरिया स्कूल के टीचर ने गुरुवार को जहर खा लिया। परिजनों ने तबियत बिगड़ने पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को गोमतीनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक टीचर काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। इसी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। गोमतीनगर इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विशाल खंड निवासी आरुणि मिश्रा ने गुरुवार को घर में जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिजनों ने बताया कि उल्टी होने पर उन्हें जानकारी हुई। डिप्रेशन के चलते काफी समय से गुमशुम थे। इसका इलाज भी कराया गया। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया।

बड़ा इमाम बाड़े पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

लखनऊ (यूएनएस)। लखनऊ में जुमा की नमाज के बाद पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ा इमाम बाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। मौलाना कल्बे जव्वाद ने पाकिस्तान के पाराचिनार में शिया नरसंहार का जमकर विरोध किया है। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान में खुले आम महिलाओं, बच्चों की हत्या हो रही है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि पाकिस्तान में 100 से अधिक बेगुनाहों का खून बहाया गया। विगत कई महीनों से निर्दोषों की हत्या का सिलसिला जारी है। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में आतंकवाद हावी है। पाराचिनार में शियों के नरसंहार पर यूएनओ समेत सभी शांति प्रिय देश खामोश तमाशा देख रहे हैं। सबसे अधिक दुख इस बात का है कि तमाम मुस्लिम संस्थाएँ और उलेमा इस क्रूरता पर चुप हैं। पाकिस्तान में यजीद के समर्थक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान सरकार आतंकवाद पर काबू पाने में नाकाम रही है और यही वजह है कि सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि हमारी मांग है यूएनओ और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इसमें हस्तक्षेप करें। मौलाना जव्वाद ने यूएनओ से इस संबंध में पाकिस्तान की जवाबदेही की मांग किया है। उन्होंने कहा कि इस अपराध के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी विषय पर कार्यशाला का आयोजन

❍ महिलाओं को महिला कल्याण विभाग की योजनाओं का मिलेगा लाभःबबीता सिंह

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज गोमती नगर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सभागार में "महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य महिला कल्याण विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समुचित जानकारी आयोग की पदाधिकारियों को देना, जिससे इन योजनाओं का और भी बेहतर ढंग से संचालन किए जाने के लिए आयोग के पदाधिकारी अपना सहयोग दे सकें और सदस्यों द्वारा की जाने वाली जनसुनवाई के दौरान इन योजनाओं का पर्यवेक्षण भी किया जा सकेगा।जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम सत्र में पुनीत कुमार मिश्र उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गयी, जिसमें पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन, 181-महिला हेल्पलाइन, वन स्टाप सेन्टर, महिला शक्ति केन्द्र, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, निराश्रित महिलाओं हेतु आश्रय सुविधा, राजकीय महिला शरणालय एवं महिला संरक्षण गृह राज्य सरकार द्वारा संचालित शक्ति सदन योजना, सखी निवास योजना, कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुयी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण व उन्नयन प्रदान किये जाने हेतु मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, बाल संरक्षण सेवाए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मिशन वात्सल्य मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनासामान्य, पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रेन आदि योजनायें शामिल हैं।आयोग की अध्यक्ष.चौहान द्वारा महिला कल्याण की ओर से उपस्थित अधिकारी को इन योजनाओं के सम्बन्ध में प्रदेश के जिलाधिकारी व निदेशक सूचना को पत्र भेजकर योजनाओं के प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार से ही प्रदेश की महिलाओं को महिला कल्याण विभाग की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सकेगा। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में महिला आयोग के पदाधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक बैठक में आयोग की अध्यक्ष द्वारा विगत माह में आयोग की पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महिला जनसुनवाई, वन स्टाप सेन्टर, महिला चिकित्सालय, महिला बन्दीगृह, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि के निरीक्षण की समीक्षा की गयी तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभाग को पत्र भेजे जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में आयोग द्वारा आगामी माह में किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया गया।कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, चारू चौधरी तथा सदस्य हिमानी अग्रवाल, सुनीता श्रीवास्तव,

अंजू प्रजापति, पूनम द्विवेदी, अनीता गुप्ता, अनुपमा सिंह लोधी, सुजीता कुमारी, मीना कुमारी, नीलम प्रभात, गीता बिन्द, गीता विश्वकर्मा, पुष्पा पाण्डेय, डॉ. प्रियंका मौर्य, मीनाक्षी भराला, ऋतु शाही, सुनीता सैनी, एकता सिंह, अर्चना पटेल, प्रतिभा कुशवाह, रेनू गौड, मनीषा अहलावत, अवनी सिंह, सपना कश्यप, संगीता जैन, पुनीत कुमार मिश्र उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, मीता पाण्डेय विधि अधिकारी उ.प्र. राज्य महिला आयोग, सहित अन्य गणमान्य पदाधिकारी,अधिकारी उपस्थित रहे।

ईवीएम मशीन भाजपा राज में नहीं आई : अठावले

योगी ने उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म की गुंडागर्दी

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले तीन महीनों में करीब 50 लोगों ने अन्य पार्टियों में अलग-अलग पदों पर रहने वाले लोगों ने आरपीआई की सदस्यता ली है। सुहेलदेव समाज पार्टी से 26, समाजवादी पार्टी से 4 और बहुजन समाज पार्टी से 20 लोग छोड़कर आरपीआई में शामिल हुए हैं। प्रदेश के जिलों से करीब 20 हजार नए सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये बात वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मीडिया से मुखातिब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. रामदास आठवले ने कही।केंद्रीय मंत्री डॉ. रामदास आठवले ने कहा कि आरपीआई उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता के नेतृत्व में 2026 में पार्टी जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रही है।आरपीआई केंद्र में एनडीए के साथ है। उत्तर प्रदेश में भी आरपीआई को अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी की तरह गठबंधन में शामिल कर प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इससे 2027 में भाजपा की और ज़्यादा सीटें आयेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है। योगी ने उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म कर दी है। विपक्ष बेकार के मुद्दों को उठाता रहता है और स्वयं की समीक्षा नहीं करता। अब राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ईवीएम को हटाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। ईवीएम भाजपा सरकार में नहीं आई। बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। बैलेट पेपर में भी एनडीए को इससे ज़्यादा सफलता मिलेगी। विपक्ष महाराष्ट्र हार गया तो ईवीएम का रोना रो रहा है लेकिन झारखंड में जीत हुई तो उस पर कुछ नहीं बोल रहा। राहुल गांधी, संविधान को लेकर भ्रम फैलाते हैं लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनके झूठ को नकार दिया। मोदी जी ने पिछले 10 साल में देश का खूब विकास किया लेकिन विपक्ष उनको इस विकास का क्रेडिट नहीं देना चाहता।

सड़कों या हाइवे पर निराश्रित गोवंश विचरण करते न पाये जाए-धर्मपाल

❍ 07 से 14 दिसम्बर तक अभियान चलाकर निराश्रित किया जाय गोवंश संरक्षण

लखनऊ (यूएनएस)। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि खेतों, सड़कों के किनारे और हाइवे पर निराश्रित गोवंश विचरण करते न पाये जाए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के साथ गोसंरक्षण कार्यों से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करने के लिए गाइडलाइन तैयार की जाए। 07 दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक सघन अभियान चलाकर प्रदेश के जनपदों में सड़कों या खेतों में घूम रहे निराश्रित गोवंश का संरक्षण किये जाने के निर्देश दिये हैं। धर्मपाल सिंह ने आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पशुधन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गौशालाओं में गोवंश के भरण पोषण की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए। अधिकारी निराश्रित गोवंश हेतु गोआश्रय स्थलों में गोवंश के ठंड से बचाव, पर्याप्त चारा, भूसा, पानी, प्रकाश, औषधि आदि आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करें। श्री सिंह ने अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि गोशालाओं में गोवंश के भरण पोषण की व्यवस्था पर पूरा अमल किया जाए। आवंटित बजट का समुचित उपयोग किया जाए। गोवंश को पर्याप्त हरा चारा दिया जाए और कोई भी गोवंश भूखा न रहने पाए। निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं संवर्द्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए और जहां से भी पशुधन के चिकित्सा की सूचना प्राप्त हो वहां तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गोवंश संरक्षण के लिए अभियान की लक्ष्य पूर्ति हेतु जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशक द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गोवंश के संरक्षण के लिए ग्राम विकास, नगर विकास, पंचायतीराज, राजस्व एवं गृह विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य किया जाए। यदि किसी विभाग द्वारा सहयोग या समन्वय नहीं किया जा रहा है तो उसकी सूचना तत्काल शासन को दी जाए।

प्रशान्त बिहार में घटित आतंकी घटना केन्द्रीय गृह मंत्रालय की सीधी असफलता

लखनऊ (यूएनएस)। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बडी विफलताओं को लेकर तीखा प्रहार किया, उन्होने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशान्त बिहार में घटित आतंकी घटना ने देश में कानून- व्यवस्था के लगातार बिगड़ते हालात को और भयावह बना गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पुलिस की अपराध शाखा से महज तीन सौ मीटर दूर व्यस्ततम इलाके में हुआ यह विस्फोट केन्द्रीय गृह मंत्रालय की सीधी असफलता है। श्री तिवारी ने कहा कि यह अत्यन्त चिंताजनक है कि रोहिणी विस्फोट के चालीस दिनों के भीतर ही प्रशांत बिहार में विस्फोट की दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है। विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मणिपुर में दस माह के मासूम बच्चे की आंख निकालकर गोली मारकर हत्या हो या फिर जम्मू में अब घाटी में भी फैला आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में देश को चिंतित किये हुए है। उन्होनें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आरोपों के घेरे में रखते हुए कहा कि यदि वह देश की कानून व्यवस्था को जबाबदेह ढंग से नही संभाल पा रहे हैं तो उन्हें संवेदनशील जिम्मेदारी के निर्वहन में अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने वायनाड से पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण को संसद के लिए एक योग्य संसदीय प्रतिभा के रूप में जनता की आवाज की मजबूती की उपलब्धि कहा है। उन्होने केन्द्र सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिटटू द्वारा प्रियंका गांधी के सांसद निर्वाचित होने को लेकर दिये गये बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के जनता से अदभुत संवाद रखने की क्षमता से भयभीत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर मोदी सरकार के मंत्री का यह बयान पूरी तरह राजनैतिक मर्यादा के विपरीत है। उन्होने कहा कि सांसद के रूप में प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी का और मजबूती से साथ देते हुए जनता से जुड़े मुददो पर इण्डिया गठबंधन की आवाज को मुखर बनायेंगी। संसद में अदाणी प्रकरण पर लगातार गतिरोध को लेकर राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने सत्तारूढ़ भाजपा को पूरी तरह से जिम्मेदार कहा है। उन्होनें कहा कि अमेरिका के न्यूयार्क अदालत में अदाणी द्वारा भारत सरकार के अधिकारियों को तेईस सौ करोड़ की रिश्वतखोरी का संज्ञान लेना देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की साख की सुरक्षा के लिए सरकार को इस बडी रिश्वतखोरी के प्रकरण पर विपक्ष की जेपीसी गठन की मांग को स्वीकार करते हुए संसद में फौरन चर्चा की नैतिकता देश के सामने रखनी चाहिए। यूपी के संभल तथा अजमेर में धार्मिक स्थलों के सर्वे के नाम पर उत्पन्न अशांति के माहौल पर राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि 1991 के धार्मिक उपासना स्थल विधेयक को पूरी तरह से लागू रखना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पार्टी द्वारा बैलेट से चुनाव की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। उन्होने कहा कि जहां ईवीएम का निर्माण हुआ है वहां भी बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। उन्होने कहा कि लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा में हर दशा में चुनाव में निष्पक्षता दिखनी चाहिए।

हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव, 11वीं सांस्कृतिक संध्या में गरबा नृत्य ने दशकों का मन मोहा

लखनऊ (यूएनएस)। स्मृति उपवन बंग्ला बाजार में आयोजित माँ गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में शुक्रवार शाम आज के बतौर मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा एवम अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह व गुंजन वर्मा द्वारा सांस्कृतिक संध्या का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। सांस्कृतिक संध्या की शुरूआत नेचुरल टच वेलफेयर सोसायटी द्वारा अध्यक्ष- स्मृति शर्मा महाराष्ट्र लोक-देव श्री गणेशा, बांग्ला-लोकगीत,राजस्थान-मैशअपध कालबेलिया, गुजराती-ढोलिडा ढोल रे वागड़ से प्रस्तुती दी गई जिसमें कुल- 53 प्रतिभागी (आर्यकन्या पाठशाला इंटर स्कूल, आरबीएन ग्लोबल स्कूल) रहें। चार प्रस्तुति में महाराष्ट्र गणेश उपासना के साथ गणेश जी स्थापना हुई, दूसरे पर बंगला, तीसरे पर राजस्थान चौथे पर गुजरात अपने प्रसिद्ध गरबा के साथ प्रस्तुति देकर भारत को अनेकता में एकता को दर्शाया। अन्त में सब प्रदेश मिल कर मंच पर शामिल हुऐ और गणेश जी को वापस उनके धाम जाने का उत्सव किया। भारत के अनेकों राज्य हैं और उनके अपने-अपने उत्सव हैं और जब उत्सव की बात आती है तो मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना की जाती है। तत्सत सेवा संस्थान सीतापुर के द्वारा सांस्कतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका संचालन अलीशा मेराज के द्वारा किया गया।

अखिलेश यादव का बयान उनकी घृणित मानसिकता को दर्शाता है : देवकी नंदन पाण्डेय

लखनऊ (यूएनएस)। अवध बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रशासन देवकी नंदन पाण्डेय ने आज यूपी प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्तालाप में कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव द्वारा निरन्तर सनातन धर्म व हिन्दू हितों की रक्षा में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं पर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है तथा उनके विरुद्ध आम जनमानस को भड़काया जा रहा है, जबकि अधिवक्ता अपने मुवक्किल की पैरवी का एक माध्यम होता है और अपने मुवक्किल की बात को तथ्य और कानून के आधार पर न्यायालय के समक्ष रखता है, जिसके पश्चात न्यायालय सभी पक्षों को सुनने के बाद नियम के तहत उचित निर्णय पारित करती है। अधिवक्ता केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है जो उसके अधिकार निहित कर्तव्य हैं, ऐसे में अखिलेश यादव द्वारा यह कहना कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन व उनके पुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा देश के अमन चौन छीनने का कार्य किया जा रहा है तथा अखिलेश यादव द्वारा उन पर दण्डात्मक व अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करना व उनके विरुद्ध ओछी टिप्पणी करना अखिलेश यादव कि घृणित मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि श्री यादव द्वारा अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का चित्र सोशल मिडिया पर लगाकर यह लिखाना की जनपद-सम्भल में हुई फसाद की जड़ वही हैं, यह बहुत निन्दनीय है जिसकी मैं कड़ी भर्तस्ना एवं निन्दा करता हूं। प्रेसवार्ता में अवध चार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ के उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्र ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता तर्क, तथ्य और कानून के आधार पर न्यायालय में कोई मुकदमा करता है या अपनी बात रखता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह अधिवक्ता का अधिकार है, परन्तु श्री यादव द्वारा राजनीतिक फायदे के लिये न्यायिक प्रक्रिया को वाधित करने का प्रयास किया जा रहा है तथा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत आलोचना की जा रही है, श्री यादव द्वारा समाज में यह फैलाया जा रहा है कि जनपद-सम्भल में दंगा अधिवक्ताओं द्वारा कराया जा रहा है, जो अनुचित व निदंनीय है। श्री यादव के इस कृत्य से अधिवक्ता व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही हैं जो स्वयं में अपराध है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन से अखिलेश यादव का व्यक्तिगत द्वेष लाजमी है, क्योंकि सन 2013 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब जनपद- बिजनौर, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर-नगर, रामपुर, मुरादाबाद, बाराबंकी में विभिन्न गम्भीर घटनाओं में पकड़े गये आतंकवादियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का आदेश उनकी सरकार द्वारा दिया गया था, परन्तु उनके मनसूबों पर पानी फेरते हुए हरि शंकर जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ में जनहित याचिका सं0.4683ध2013 (सुश्री रंजना अग्निहोत्री वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया) दाखिल किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ ने आतंकवादियों के ऊपर लगे मुकदमों को वापस लेने पर रोक लगा दिया था और अखिलेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय विरोधी एवं तुष्टिकरण के कार्य में सफलता नहीं मिली थी, इसलिये भी श्री अखिलेश यादव वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन से व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन व उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा मो०. अली जौहर विश्वविद्यालय के विषय पर भी याचिका योजित की गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन को सफलता प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन द्वारा जीम च्संबमे वॅर्वतीपच (ैचमबपंस च्तवअपेपवद), ।बज 1991 की वैधता को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है जिसमें केन्द्र सरकार को नोटिस जारी हुई है, यह मुकदमे न्यायालय में लंबित है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन द्वारा जीमॅुि ।बज, 1995 की वैधता को चुनौती देते हुए देश के अलग-अलग माननीय उच्च न्यायालय में लगभग 120 याचिकायें दाखिल की गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा जहां-जहां धर्म और राष्ट्रीय हित के खिलाफ बनाये गये कानून पाये गयें है, उसके खिलाफ विधिक लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ी जा रही है। श्री जैन केवल मन्दिर, मस्जिद इत्यादि के अलावा भी जनहित के तमाम महत्वपूर्ण मुकदमे करते हैं, जिस कारण अखिलेश यादव द्वारा उनको दंगा भड़काने वाला कहना अनुचित नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा विधि के क्षेत्र में न्यायालय के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा कभी भी कोई गैर विधिक प्रक्रिया नहीं की गई है। जहां तक जीम च्संबमे वॅर्वतीपच (ैचमबपंस च्तवअपेपवद), ।बज 1991 की वात है यह एक्ट हर जगह लागू नहीं होता है लेकिन अज्ञानता में लोग इसकी दुहाई देते रहते हैं। जहां तक मन्दिरों से जुड़े मकदमों की बात है जब किसी मन्दिर की स्थापना हो जाती है तो वह अनन्तकाल तक रहती है, यह बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम मन्दिर में दिये गये निर्णय में कही है तथा इसका उत्लेख धर्मशास्त्रों में भी है तथा मन्दिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है और यदि अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो तोड़े हुए मन्दिर पर पुनः मन्दिर का निर्माण होना चाहिये।

लखनऊ में एलडीए की तरफ से विहंग उत्सव, वेटलैंड में बर्ड वाचिंग

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी लखनऊ में एलडीए की तरफ से विहंग उत्सव का आयोजन किया गया है। बर्ड वाचिंग से कार्यक्रम की शुरुआत मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने की। सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने पर्यावरण प्रकृति, वेटलैंड, बर्ड प्रोटेक्शन के विषय पर पेंटिंग बनाई। इसके साथ ही इनवायरमेंट प्रोटेक्शन विषय पर क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बर्ड वॉचिंग की है। मौके पर वेट लैंड में पक्षियों के रहने के लिए जरूरी उपाय करने का भी निर्देश दिया। वॉच टावर से इस दौरान अधिकारियों और स्कूली बच्चों से प्रवासी पक्षियों की अठखेलियों को देखा है। मौके पर मंडलायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया है। वेट लैंड में स्कूली छात्रों ने बर्ड वॉचिंग हाईड, वॉच टावर और व्यूइंग डेक का खूबसूरत नजारा देखा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने सीजी सिटी (चक गंजरिया) में इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पीछे 37 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में वेट लैंड विकसित किया है, जोकि लखनऊ में ईको टूरिज्म का केन्द्र है। वेट लैंड से शहर में कई प्रकार के स्वदेशी व विदेशी पक्षियों के प्राकृतिक वास को बढ़ावा मिला है। वर्तमान में कई अलग-अलग प्रजतियों के पक्षियों ने यहां डेरा डाल रखा है।

अमृत कलश टाइम्स
हिन्दी दैनिक

जंक्शन पर एनसीआर का प्रथम गेमिंग जोन बनेगा

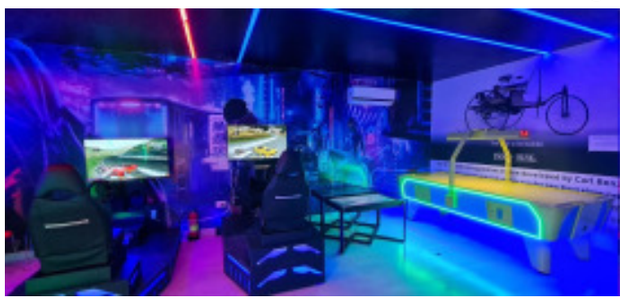

प्रयागराज। मण्डल यात्रियों को रेलवे का सुखद अनुभव देने के लिए सुविधाओं को निरंतर बेहतर कर रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 6 के निकट उत्तर मध्य रेलवे का पहला गेमिंग जोन शुरू

किया जाएगा । यह गेमिंग जोन हाई–एंड गेमिंग वीआर क्रिकेट बॉक्स, मोशन थिएटर, पीसी गेम्स, आर्केड गेम्स, जंगल सफारी, एयर हॉकी और वीआर गेम्स से लैस होगा । यात्री क्लासिक से लेकर आधुनिक आर्केड गेम्स तक कई तरह के खेलों का आनंद ले सकते हैं। यह जोन यात्रियों को मनोरंजन का अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह गेमिंग जोन फन स्पेस एलएलपी द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह गेमिंग जनवरी, 2025 से अपनी सेवाएं प्रारंभ कर देगा। प्रयागराज जंक्शन पर गेमिंग जोन की अभिनव सुविधा न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि बच्चों, वयस्कों और वृद्धों जैसे सभी आयु समूहों के लिए भी इसका अनुभव बेहतर होगा। गेमिंग जोन 24ध्7 खुला रहेगा, और यात्री निध्ाारित शुल्क पर टिकट खरीदकर इसका उपयोग कर सकेंगे । यह गेमिंग जोन मॉल में बने गेमिंग जोन की तर्ज पर बनाया जाएगा । यह पहल यात्रियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने और सुविधाओं को आधुनिक व उन्नत करने के प्रयागराज मण्डल के प्रयासों का हिस्सा है। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग हिमांशु शुक्ला ने कहा कि प्रयागराज मण्डल यात्रियों के लिए उच्च कोटि की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रयागराज जंक्शन पर एग्जीक्यूटिव लाउंज और स्लीपिंग पॉडस जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा चुकीं हैं। उत्तर मध्य रेलवे के पहले गेमिंग जॉन के लिए निविदा और एग्रीमेन्ट प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।

निगम ने अतिक्रमण के दौरान शमन शुल्क वसूला।

प्रयागराज। बेली अस्पताल से लेकर लालालाजपथ राय मार्ग होते हुए मण्डलायुक्त कार्याल से मजार चौराहा तक नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया तथा अतिक्रमण से पहले व अतिक्रमण के हटाने के बाद की फोटोग्राफी करायी गयी एवं दोनों तरफ की पटरियों साफ करायी तथा कुल जुर्माना रू0–47,500ध– शमन शुल्क वसूला गया। अतिक्रमण हटाने में थाना कर्नलगंज, प्रयागराज का सहयोग लिया गया। तथा इस सम्बन्ध में कर्नलगंज थाने को अवगत करा दिया गया है कि शासनादेशानुसार उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण न हो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित थाने की है। साथ ही साथ दिनांक–27.11.2024 को मुख्यमंत्री उप्र एवं मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के प्रयागराज आगमन पर अतिक्रमण हटाने हेतु पी०डी०टण्डन रोड़ से लेकर एकलव्य चौराहा होते हुए स्वामी विवेकानन्द चौराह व धोबीघाट चौराह, राणा प्रताप चौराहा, सरदार पटेल मार्ग, सुभाष चौराहा तथा खरमन्दा मार्केट तक एवं द्वितीय टीम के द्वारा भी बालसन से लेकर बक्शीबांध होते हुए नागवाशुकी मन्दिर, दशासुमेरघाट, गंगा रिवरफ्रेन्ट लेकर संगम नोज तक व तृतीय टीम भी एकलव्य चौराहा से लेकर ए.जी.आफिस से होते हुए इंदिरा मूर्ति चौराहा, थार्नहिल रोड, हीरा हलवाई तक एवं चतुर्थ टीम के द्वारा भी चौफटका से लेकर कर्बला चौराहा, राजरूपपुर, झलवा, पीपलगाँव तक नगर निगम, प्रयागराज द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया, तथा अतिक्रमण से पहले व अतिक्रमण के हटाने के बाद की फोटोग्राफी करायी गयी एवं दोनों तरफ की पटरियों साफ करायी तथा कुल जुर्माना रू0–12,200ध– शमन शुल्क वसूला गया। अतिक्रमण हटाने में थाना सिविल लाइन्स, कैंट, दारागंज, धूमनगंज, खुल्दाबाद एयरपोर्ट थाना–प्रयागराज का सहयोग लिया गया, तथा इस सम्बन्ध में सिविल लाइन्स थाने को अवगत करा दिया गया है कि शासनादेशानुसार उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण न हो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित थाने की है।

उत्तर मध्य रेलवे

निविदा सूचना संख्या:- 27-विद्युत/सा०/प्रयागराज/24-25 दिनांक- 20.11.2024

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य) उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज निर्धारित प्रपत्र पर निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा दिनांक 18.12.2024 समय 15:00 बजे तक आमंत्रित करते हैं निविदा सम्बंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित है -

क्रम सं.: 1	निविदा सूचना संख्या : ELG-50-2425
कार्य का नाम: सीएनबी में एआटी कर्मचारियों के लिए 06 यूनिट टाइप-II, 06 यूनिट टाइप-III, 04 यूनिट टाइप - IV और 02 यूनिट टाइप-V क्वाटरों के प्रावधान के संबंध में विद्युत कार्य।	
काम की लागत (रू० में) : 3753760.28	बिड सिक्योरिटी (रू० में) : 75100.00
क्रम सं.: 2	निविदा सूचना संख्या : ELG-51-2425
कार्य का नाम: "कानपुर सेंट्रल में हॉस्टल बिल्डिंग का विस्तार और एमडीडीटीआई/सीएनबी में भोजनालय क्षमता का विस्तार" से संबंधित विद्युत कार्य। "प्रयागराज मंडल के बीआरएन-ईटीएच सेक्शन में 02 गेट संख्या 19सी (एसडब्ल्यूडब्ल्यू-जेएससी), 33सी (जेएससी-केडब्ल्यूडब्ल्यू) की इंटरलॉकिंग।", कंचौसी रेलवे स्टेशन पर ओएमआरएस हट की विद्युत आपूर्ति का प्रावधान।" "पीआरवाईजे और सीएनबी में एआरटी की स्टेबलिंग सुविधा के साथ ब्रेकडाउन क्रेन शेड" से संबंधित विद्युत कार्य।	
काम की लागत (रू० में) : 10686936.80	बिड सिक्योरिटी (रू० में) : 203400.00
क्रम सं.: 3	निविदा सूचना संख्या : ELG-52-2425
कार्य का नाम: टीडीएल-एफजेडडी सेक्शन में लिफ्ट का प्रावधान। (चरण-I)। PRYJ-CNB सेक्शन में लिफ्ट का प्रावधान।(चरण-1)। CNB-ETW सेक्शन में लिफ्ट का प्रावधान। (चरण-1)। प्रयागराज डिवीजन के सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का प्रावधान। जीएम एनसीआर ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूबेदारगंज में 04 लिफ्ट का प्रावधान। पुराने जीएम बिल्डिंग/सीपीआरओ ऑफिस PRYJ में 02 लिफ्ट का प्रावधान। प्रयागराज डिवीजन में अमृत भारत और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए लिफ्ट का प्रावधान। "डीईआर स्टेशन और एनटीपीसी/डीईआर के बीच एलसी गेटों की मैनिंग" के संबंध में विद्युत कार्य।	
काम की लागत (रू० में) : 6742964.18	बिड सिक्योरिटी (रू० में) : 134900.00
क्रम सं.: 4	निविदा सूचना संख्या : ELG-53-2425
कार्य का नाम: "भरवारी (बीआरई) स्टेशन पर 20 बिस्तरों वाले नए आरपीएफ बैरक और सुबेदारगंज (एसएफजी) स्टेशन पर आरपीएफ थाने का प्रावधान" से संबंधित विद्युत कार्य। एसएंडटी उपकरणों के जीवन को बढ़ाने और सुचारू संचालन के लिए वीडीयू रूम/एसएम चैंबर में एयर कंडीशनर का प्रावधान। "ट्रेन संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए 14 वे साइड स्टेशनों पर पुरुष और महिलाओं के लिए सामान्य विश्राम कक्ष का प्रावधान" से संबंधित विद्युत कार्य। रूमा स्टेशन प्राग-सीएनबी सेक्शन में नए स्टेशन भवन के निर्माण से संबंधित विद्युत कार्य।	
काम की लागत (रू० में) : 26153205.63	बिड सिक्योरिटी (रू० में) : 280800.00

कार्य समाप्त करने की समयावधि : 06 माह, निविदा खुलने की तिथि: 18.12.2024, समय- 15:00 बजे। नोटः- उपरोक्त ई-टेंडर के साथ पूरी जानकारी (निविदा दस्तावेज के साथ) वेबसाईट www.ireps.gov.in पर 15:00 बजे निविदा खोलने की तिथि तक उपलब्ध है। 2058/24 (AS)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

AI की नजर... पूरे शहर की है नगर निगम को खबर

–प्रयागराज नगर निगम में बना यूपी का पहला सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट कंट्रोल रूम

–शहर की सफाई से लेकर लोगों की समस्याओं का किया जा रहा त्वरित समाधान

प्रयागराज। अतिक्रमण की समस्या है या स्ट्रीट लाइट है खराब। समय पर कूड़ा नहीं उठ रहा या अवैध निर्माण की है बात। अब प्रयागराज के लोगों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रयागराज नगर निगम ने इन समस्याओं को दूर करने और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के सहयोग से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल रूम तैयार किया है । इस तरह का सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट कंट्रोल रूम पूरे प्रदेश में पहली बार विकसित किया गया है । नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उन सभी की रियल टाइम मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से की जा रही है ।

आईसीसीसी से जुड़ा है कंट्रोलरूम

नगर निगम परिसर में तैयार हुआ कंट्रोलरूम आईट्रीपलसी के साथ जुड़ा है । इससे शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर लगे सीसीटीवी के जरिए पूरे शहर पर निगम की तरफ से निगरानी की जा रही है । AI की मदद से सड़कों पर झाड़ू लगने, कूड़ा हटने, कूड़ा उठाने वाले वाहनों की ट्रैकिंग और डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले वाहनों की ट्रैकिंग भी यहीं से हो रही है। सिटी स्वीपिंग, पब्लिक टॉयलेट्स और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की निगरानी के साथ कचरे के ढेर, गंदगी, या अन्य सफाई संबंधी समस्याओं की जानकारी होने पर तुरंत उनका समाधान भी किया जा रहा है । कंट्रोल रूम से सफाई व्यवस्था से जुड़ी हर गतिविधि पर तो नजर रखी ही जा रही है । साथ ही आमजन की समस्याओं को देखते हुए निगम की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम भी किया जा रहा है।

अतिक्रमण करने वालों पर भी लगेगी लगाम

शहर में अतिक्रमण, सड़क किनारे पड़े कूड़े और खराब स्ट्रीट लाइट की निगरानी AI आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से की जा रही है । जहां भी कमियां पाई जा रही है, वहां कंट्रोल रूम से कॉल कर जोनल अधिकारियों और सफाई निरीक्षकों को आदेशित कर तुरंत उसका निस्तारण करवाया जा रहा है । प्रतिदिन 70 किलोमीटर तक मुख्य सड़कों के दायरे को कवर किया जा रहा है । अत्याधुनिक कैमरे से लैस नगर निगम के दो वाहन 35–35 किमी सुबह और शाम शहर की सड़कों पर चलाए जा रहे हैं । इसमें लगे AI कैमरे सड़क किनारे पड़े कूड़े, खराब स्ट्रीट लाइट, सड़क के गड्ढों और अतिक्रमण की तस्वीर कैद कर नगर निगम में बने कंट्रोल रूम को भेज रहे हैं।

54 से अधिक समस्याओं का हुआ निस्तारण

कंट्रोल रूम के अनावरण के पहले AI कैमरे के जरिए निगरानी शुरू कर दी गई थी ।15 दिन में खराब स्ट्रीट लाइटों और जीवीपी पॉइंट की सफाई करने समेत 54 से अधिक समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है । वाहन पर लगे AI कैमरे समस्या से जुड़ी तस्वीर कंट्रोल रूम भेज रहे हैं और 24 घंटे में उन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

AI कैमरे का उपयोग कर इन समस्याओं पर रखी जा रही है नजर

- खराब स्ट्रीट लाइट चिह्नित करने के लिए
- सड़कों के गड्ढे चिह्नित करने के लिए
- जीवीपी पॉइंट को चिह्नित करने के लिए
- अवैध होर्डिंग्स
- अतिक्रमण
- सड़कों पर छुट्टा जानवरों की समस्याओं के निस्तारण के लिए

कंट्रोल रूम से हम पूरे शहर की सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सड़क के गड्ढों, खराब स्ट्रीट लाइटों, अवैध होर्डिंग्स जैसी समस्याओं की जानकारी एआई के माध्यम से होने पर उनका भी त्वरित समाधान किया जा रहा है।

चन्द्र मोहन गर्ग
नगर आयुक्त
नगर निगम प्रयागराज

एनसीआरः महाकुंभ रेल महोत्सव-२०२५ का आयोजन

प्रयागराज। मण्डल द्वारा 'महाकुंभ रेल महोत्सव–2025' के अंतर्गत प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या –1 के बाहरी प्रांगण में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया । सांस्कृतिक संध्या का आयोजन 28 फरवरी, 2025 तक प्रत्येक गुरुवार को किया जाएगा। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से राकेश जायसवाल, मीरा जायसवाल, धर्मेन्द्र, बृहस्पति पांडे एवं रुपाली जैन ने शानदार प्रस्तुतियां दीं। रंजीत सिंह, आकाश कुमार, अनिल कुमार एवं शैलाग्य सिन्हा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाद्य यंत्रों से कलाकरों को साज दिया और समा बांध दिया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर हैं। इस संस्था के 180 से अधिक देशों में केंद्र हैं। दिन प्रतिदन के तनाव और खिंचाव के बीच खुश रहकर जीवन का आनंद लेना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। यह एक तकनीक है, जिसके माध्यम से तनाव और चिंताओं को दूर कर जीवन में खुशी और आनंद लाने की कला सीखी जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था चिन्ता, अवसाद व तनाव से मुक्ति एवं आत्म–विकास के लियें कार्य करता है। अपर मण्डल रेल प्रबंधक इन्फ्रा नवीन प्रकाश, वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी–प्प वैभव गुप्ता एवं महिला कल्याण समितिध प्रयागराज की अध्यक्षा निधि बडोनी भी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम का मंच संचालन मिथलेश कुमार ने किया। प्रयागराज मण्डल, महाकुंभ–2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को शानदार, सुखद और यादगार बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा व जागरूकता के लिए प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, नैनी एवं सूबेदारगंज स्टेशनों पर की गयी तैयारियों एवं योजना के बारे में मण्डल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी। ष्महाकुंभ रेल महोत्सव–2025ष में गायन, नृत्य एवं काव्य पाठ में रुचि रखने वाले स्वैच्छिक प्रतिभागी बनने के लिए अपनी कला का वीडियो क्लिप (रंजीत सिंह (मो– 9335577217) को व्हाट्सएप पर अथवा ईमेल welfarencr2490@gmail-com पर अथवा हित अनुभाग कक्ष संख्या 46, प्रथम तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रयागराज पर भेज सकते है। जिसकी सांस्कृतिक टीम द्वारा स्क्रीनिंग किए जाने के उपरांत सांस्कृतिक संध्या में कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु आमंत्रित किया जाएगा । कार्यक्रम में सहभागिता का आवेदन व्यक्ति, समूह, शैक्षिक संस्था, स्कूलध्कॉलेज, विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को रेल विभाग द्वारा प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित भी किया जाएगा।

'कालाकल्प' कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कुलगीत प्रस्तुत की।

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव के चार वर्षों के सफल कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सिनेट हाल में कायाकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरंभ में संगीत विभाग के विद्यार्थियों ने कुलगीत प्रस्तुत किया। इसके बाद सभी संकायों और विभागों के अध्यक्षों और शिक्षकों ने पुष्पगुच्छ देकर कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव का स्वागत किया।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत कैरियर मेले का शुभारंभ

प्रयागराज। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कैरियर मेले का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री के द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन देने के लिए पंख पोर्टल का संचालन प्रारंभ किया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं यूनिसेफ की सहायता से संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में अध्यनरत छात्र–छात्राओं को कैरियर के बारे में निरूशुल्क मार्गदर्शन प्रदान करना है। कैरियर मेले का शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक पी.एन. सिंह के द्वारा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलनके साथ किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्या नीलम मिश्रा के द्वारा मुख्य अतिथि, अभिभावकों एवं सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने छात्राओं को करियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। अभिभावकों एवं छात्राओं को अभिप्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का है। हमें अपने बच्चों की क्षमताओं एवं रुचियों का ध्यान रखते हुए उच्च अध्ययन के क्षेत्र एवं करियर का चुनाव करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं, छात्राएं एवं कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित थे।कैरियर मेले में जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों और कॉलेज के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के द्वारा अपनी संस्था से संबंधित स्टाल लगाए गए ।सभी छात्राओं और अभिभावकों ने विभिन्न स्टालों पर जाकर करियर के बारे में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी प्राप्त की। मेले में हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट, मॉडल करियर सेंटर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी, एच एम एफ ए मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हंडिया, उर्मिला महिला महाविद्यालय, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस ,एलडीसी ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस के विशेषज्ञ और प्रतिनिधियों ने विभिन्न कैरियर क्षेत्रों के बारे में छात्राओं और उनके अभिभावकों को मार्गदर्शन प्रदान किया। अतिथियों में जिला समन्वयक कुमुद श्रीवास्तव, डॉक्टर सपना चौधरी, डॉ आकाश जायसवाल, डॉक्टर सुग्रीव सिंह ,जय प्रकाश सिंह, हरिओम पांडे , डॉ रत्नेश दीक्षित अनीश कनौजिया, सुमन पांडे, अंजलि जादौन, डॉ लकी मिश्रा, सुधीर द्विवेदी, विमलेश श्रीवास्तव,पूजा पोरवाल, अंजू त्रिपाठी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन पंख पोर्टल प्रभारी डॉ मधु यादव एवं वंदना आनंद ने किया। लता कुमारी, किरन राय, प्रज्ञा मिश्रा का सक्रिय सहयोग रहा।

आगामी महाकुम्भ के कार्यो का निरीक्षण किया

प्रयागराज। आगामी महाकुंभ के दृष्टिगत प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा मजार चौराहे, तेलियरगंज चौराहे एवं महिला ग्राम चौराहे (चौफटका) पर कराए जा रहे। चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण शुक्रवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कॉन्ट्रैक्ट की सीमा पूरी हो जाने के पश्चात् भी कार्यों की प्रगति धीमी पाई। तेलियरगंज चौराहे के निरीक्षण के दौरान भी कॉन्ट्रैक्ट की सीमा पूरी हो जाने के पश्चात् भी कार्यों की प्रगति धीमी पाई गई। मण्डलायुक्त ने कार्यों में शिथिलता बरतने तथा कॉन्ट्रैक्ट की सीमा पूरी हो जाने के पश्चात् भी कार्यों की प्रगति धीमी होने पर सम्बंधित अधिकारी को ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए हैवी पेनाल्टी लगाने (लिक्यूडेशन डैमेज लेने) तथा दोनों चौराहों के अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता को एडवर्स एंट्री देने के निर्देश दिए। पीडीए सचिव अजीत सिंह उपस्थित रहे।

सम्पादक
सिद्धनाथ द्विवेदी
प्रबन्धक निदेशक
दीपक जयसवाल
सम्पादकीय कार्यालय
11ई/2, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के आधीन होगा।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक सिद्धनाथ द्विवेदी द्वारा काम्पीटेंट बिजनेस सर्विसेज विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित एवं 399 कृष्णानगर कीडगंज से प्रकाशित।
सम्पादक–सिद्धनाथ द्विवेदी, आरएनआई नं. UPHIN/2007/22706 रजि.नं. AD-32/2008-09 ईमेल: amritkt.alld@gmail.com फोन नं. : 9453273951, 8799627062